

भारत-अमेरिका संबंध: India-US Relations

भारत-यू.एस. साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हितों के बढ़ते अभिसरण के आधार पर द्विपक्षीय संबंध एक "वैश्विक रणनीतिक साझेदारी" के रूप में विकसित हुए हैं। ऐतिहासिक रूप से, यू.एस. ने भारत की शक्ति के विकास के लिए एक द्विपक्षीय दृष्टिकोण बनाया। एक ओर, इसने भारतीय स्थिरता को महत्व दिया और उन पहलुओं को बढ़ावा दिया जो इसके बड़े हितों की सेवा करते थे। यह उस समय अमेरिका की उदारता की व्याख्या करता है जब विकास कार्यक्रमों की बात आती है जब हमारे राजनीतिक संबंध अपने सबसे अच्छे रूप में नहीं थे। जब 1962 जैसी गंभीर चुनौतियां थीं, तो अमेरिकी नीति निर्माता वास्तव में हमारे भविष्य को लेकर चिंतित थे। लेकिन दूसरी ओर, उन्होंने हमारे क्षेत्रीय प्रभुत्व को बेअसर करने के लिए काम किया, विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ कुछ समानता सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की।

भारत में नई सरकार द्वारा विकास और सुशासन पर जोर देने से द्विपक्षीय संबंधों को फिर से मजबूत करने और नए आदर्श वाक्य "चलें साथ साथ: फॉरवर्ड टुगेदर वी गो" के तहत सहयोग बढ़ाने का नया अवसर पैदा हुआ है, जिसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के पहले शिखर सम्मेलन के बाद 30 सितंबर 2014 को वाशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ अपनाया गया था। उच्च स्तरीय राजनीतिक यात्राओं के नियमित आदान-प्रदान ने द्विपक्षीय सहयोग को निरंतर गति प्रदान की है, जबकि व्यापक और निरंतर विस्तारित संवाद वास्तुकला ने भारत-यू.एस. के लिए एक दीर्घकालिक ढांचा स्थापित किया है।

आज भारत-यू.एस. द्विपक्षीय सहयोग व्यापक-आधारित और बहु-क्षेत्रीय है, जिसमें व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, उच्च-प्रौद्योगिकी, असैनिक परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग, स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि और स्वास्थ्य शामिल हैं।

भारत-अमेरिका संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

राष्ट्रपति हैरी एस. ट्रूमैन के नेतृत्व में अमेरिका ने उत्साहपूर्वक भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन किया। उन्होंने अपने ब्रिटिश सहयोगियों पर भी विजय प्राप्त की, जिसमें प्रधान मंत्री क्लेमेंट एटली भी शामिल थे, जो अंततः भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूदा स्थिति के आगे झुक गए। भारत 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्र हुआ। हालाँकि, दोनों देशों ने स्वतंत्रता के बाद के अधिकांश विदेश नीति निर्णयों के विपरीत स्पेक्ट्रम पर खुद को पाया। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने सक्रिय रूप से भारत को अपने शिविर में शामिल होने के लिए प्रभावित करने की कोशिश की। भारत ने दृढ़ता से किसी भी शिविर में शामिल होने से इनकार कर दिया और अपनी 'गुटनिरपेक्ष आंदोलन नीति' को फिर से लागू किया। ऐसा करके, उसने अपनी 'रणनीतिक स्वायत्तता' को लागू किया और वर्तमान समय में भी ऐसा करना जारी रखा।

भारत को इसकी भारी कीमत तब चुकानी पड़ी जब 1971 के युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का समर्थन किया और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर भी। जब भारत में बड़े पैमाने पर अकाल पड़ा, तो अमेरिका ने खाद्य सहायता (विशेषकर



गेहूँ) के उसके अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया। उत्तरार्द्ध ने PL-480 कानून का उपयोग करके राष्ट्रों को अपने शिविर में फंसाने की मांग की 1991 में यूएसएसआर के विघटन ने अमेरिका और उसके अन्य सहयोगियों जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया और इज़राइल के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत किया।

अमेरिकी प्रशासन ने इसरो जैसे कई भारतीय संगठनों को मंजूरी दी, और भारत के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को भी भारी मंजूरी मिली। अंत में, 2006 में, दोनों देशों ने प्रसिद्ध भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत किया।

सामरिक भागीदारी

शुरुआत करने के लिए, अमेरिका उन कुछ देशों में से एक है जिनके साथ भारत ने व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और एक 2+2 संस्थागत संवाद तंत्र है (वर्तमान में, भारत के पास सभी QUAD देशों- जापान और के साथ 2+2 रणनीतिक वार्ता है।) यह रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में और 'रणनीतिक डोमेन' में अपने सहयोग को बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए दोनों देशों का लगभग एक साझा दृष्टिकोण है।

भारत-अमेरिका वार्ता

भारत-अमेरिका की दोनों सरकारों के बीच 50 से अधिक द्विपक्षीय वार्ता तंत्र हैं। विदेश मंत्री और राज्य मंत्री (वाणिज्य एवं उद्योग) के स्तर पर सामरिक और वाणिज्यिक वार्ता की पहली दो बैठकें सितंबर 2015 में वाशिंगटन डीसी और अगस्त 2016 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस शीर्ष-स्तरीय वार्ता ने द्विपक्षीय भारत-अमेरिका संबंधों के पांच पारंपरिक स्तंभों में एक वाणिज्यिक घटक जोड़ा है, जिस पर विदेश मंत्रियों की पूर्ववर्ती रणनीतिक वार्ता ने निम्न बिन्दुओं पर ध्यान केंद्रित किया था,

- सामरिक सहयोग;
- ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन,
- शिक्षा और विकास;
- अर्थव्यवस्था, व्यापार और कृषि; विज्ञान और तकनीक; तथा
- स्वास्थ्य और नवाचार।

सामरिक और वाणिज्यिक वार्ता की दूसरी बैठक 30 अगस्त 2016 को नई दिल्ली में हुई। इसमें मंत्री स्तरीय संवाद के अलावा निम्न बिंदु शामिल थे:

- होम (होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग),
- वित्त (वित्तीय और आर्थिक भागीदारी),
- वाणिज्य (व्यापार नीति फोरम),
- एचआरडी (उच्च शिक्षा संवाद),
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी पर संयुक्त आयोग की बैठक) और



- ऊर्जा (ऊर्जा संवाद)।

भारत-अमेरिका संबंधों में चुनौतियां

ईरान और रूस के साथ भारत के बहुआयामी संबंधों को संतुलित करने में चुनौतियां रही हैं। भारत को ईरान और रूस से रियायती तेल आयात को रोकने के लिए मजबूर किया गया है, और इन भारी-भरकम अमेरिकी रणनीति के कारण भारत के तेल आयात बिल में तेज वृद्धि हुई है। भारत-अमेरिका के हित तब टकरा गए जब भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों की धमकियों के बावजूद रूसी निर्मित S-400 ट्रायम्फ़ मिसाइल रक्षा प्रणाली का फैसला किया। भारत अमेरिका संबंधों में अन्य निम्न प्रकार से हैं:

अमेरिका-पाकिस्तान संबंध: भारत और पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को डी-हाइफ़न करने के वाशिंगटन के दावों के बावजूद, अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने जटिल गठबंधन की देनदारियों से खुद को मुक्त नहीं कर पाया है।

व्यापार विवाद अमेरिका ने हाल ही में भारत को अपने सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (जीएसपी) कार्यक्रम से हटा दिया, जिसका भारत एक बड़ा लाभार्थी था। अमेरिका ने भारतीय निर्यात को प्रभावित करने वाले स्टील और एल्युमीनियम उत्पादों पर शुल्क लगाया भारत को अमेरिका द्वारा "टैरिफ़ किंग" के रूप में संदर्भित किया गया है जो "अत्यधिक उच्च" आयात शुल्क लगाता है।

डब्ल्यूटीओ विवाद: भारत यूएसए, भारत द्वारा चिकित्सा उपकरणों की कीमतों को सीमित करना, अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों आदि के लिए भारतीय बाजार में अधिक पहुंच जैसे मुद्दों पर डब्ल्यूटीओ विवादों में शामिल है।

आईपीआर संघर्ष: भारत अमेरिका की "प्राथमिकता निगरानी सूची" में भी है जो अमेरिकी बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए चुनौतियों का सामना करने वाले देशों की पहचान करता है। भारत के लिए करेंसी मैनिपुलेटर टैग - हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को मुद्रा में हेराफेरी करने वाले देशों की 'निगरानी सूची' में शामिल किया।

भारत में आंतरिक मुद्दे: अमेरिकी कांग्रेस और अमेरिकी नागरिक समाज के कुछ हिस्सों की आलोचना अमेरिकी प्रशासन को भारत को कश्मीर को सामान्य स्थिति में लाने और एनआरसी के बाद नए नागरिकता कानून के साथ आगे नहीं बढ़ने के लिए कह रही है। अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा मानवाधिकार रिपोर्ट - उल्लेख किया गया है कि भारत में कई मानवाधिकार मुद्दे हैं जैसे कि अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, हिंसा से जुड़े अपराध और अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों को लक्षित करने वाले भेदभाव आदि।

अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने भारत को विशेष चिंता वाले देश (सीपीसी) के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश की। इसने भारतीय व्यक्तियों और संस्थाओं पर 'धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर



उल्लंघन' के लिए लक्षित प्रतिबंधों की भी सिफारिश की। अमेरिका ने नई दिल्ली से अनुमति लिए बिना भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन (FONOP) किया।

21वीं सदी में विश्व व्यवस्था को आकार देने के लिए भारत और अमेरिका के बीच संबंध महत्वपूर्ण हैं। सहयोग की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए, दोनों सरकारों को अब अधूरे समझौतों को अंतिम रूप देने और व्यापक रणनीतिक वैश्विक साझेदारी के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए काम करना चाहिए। इस संबंध को फलने-फूलने के लिए विभिन्न राजनयिक विकल्पों के साथ निरंतर पोषित किया जाना चाहिए।

